(क) राजस्थान के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस देने का मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ? और

(ख) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जिलेबार जानकारी नहीं रखी जाती है । फिर भी दिनांक 30 सितम्बर, 1972 को राज स्थान में नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु 74 आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन थे ।

(ख) औद्योगिक आवेदनों पर विचार करते समय प्रस्तावक के विभिन्न पहलुओं पर अधिक ब्यौरेवार परीक्षण की आश्यकता पड़ती है । किसी भी विशेष आवेदन पत्र के कारणों से बिलम्ब लग जाता है जो सरकार के नियंत्रण के परे होते हैं जैसे आवेदन पत्रों में प्रथम : पूरी जानकारी नहीं होती है। अपेक्षित जानकारी मंगानी पड़ती है । कभी कभी समग्र उद्योग के बारे में नीति सम्बन्धी निर्णय लेने होते हैं तो भी, सरकार पड़े हुए आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के सुनिश्चय के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रही है ।

**श्री हरिकोट राकेट रेंज से एक उपग्रह का छोड़ा जाना**

1313. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद के निकट श्री हरिकोटा स्थान पर भारतीय राकेट से एक भारतीय उपग्रह छोड़े जाने की योजना कब बनी थी ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : भारत में निर्मित एक उपग्रह को छोड़ने की सम्भाव्यता का अध्ययन अप्रैल, 1968 में शुरू किया गया था । नवम्बर, 1968 में यह निश्चित हो गया कि भारत-निर्मित उपग्रह छोड़ा जा सकता है । राकेट तथा उपग्रह के डिजाइन का अध्ययन अभी जारी है ।

**Distribution of Soviet News in India**

1314. SHRI BHALJIBHAI PARMAR:
SHR SATYENDRA NARAYAN SINHA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be please to to state:

(a) whether the United News of India has entered into an agreement with the Soviet news agency "Tass" for disributing Soviet news in India; and

(b) if so, the financial benefit that the U.N.I. is to get from this?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA): (a) Yes, Sir.

(b) U.N.I. have requested that since the arrangements between U.N.I. and TASS are commercial in nature, it would must not be appropriate to make them public.